आठ डाटा सेंटर होंगे स्थापित आएगा 40,000 करोड़ का निवेश

- सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़
- प्रदेश में तीन सेंटर आफ एक्सीलेंस की भी होगी स्थापना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बजट में सरकार ने आठ डाटा सेंटरों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। साथ ही सेमीकंडक्टर नीति के तहत इस क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रविधान किया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने डाटा सेंटरों की स्थापना के जरिए 40,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई है। इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रदेश को डाटा सेंटर उद्योग के रूप में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बजट में अधिसूचित नई इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत राज्य में तीन सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। डाटा सेंटर के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने 2021 में उप्र डाटा सेंटर नीति लागू की थी जिसके तहत निवेशकों द्वारा लगभग 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है और तीन लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। तीन डाटा सेंटर से बढ़ाकर आठ डाटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य किया गया है।

आठ डाटा सेंटरों की स्थापना के बाद 900 मेगावाट डाटा डाटा एकत्र किया जा सकेगा। नई सेमीकंडक्टर नीति के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की व्यवस्था को ओडिशा और गुजरात की नीति का अध्ययन करने के बाद की गई है। सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इको सिस्टम का स्थापित किया जाए। भारत में वर्ष 2025 तक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की मांग 100 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंचने की संभावना है।

डाटा सेंटर प्रतीकात्मक चित्र